DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, APRIL 20, 2023 ----------DATED----------

Faceless system to cut graft, speed up property work

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: The registration of land deeds, wills, lease and rent agreements and other documents at the sub-registrar offices will revolutionise with the revenue department adopting National Generic Document Registration System (NGDRS) in the capital.

Lieutenant governor VK Saxena, who had called a meeting to review the functioning of 22 sub-registrar offices headed by women officers, directed for the same to be implemented at the earliest following persistent complaints of harassment and corruption.

The "faceless" system will make it easier for people to upload the necessary documents for registration of sale deeds, power of attorney and wills from the comfort of their home, make payment and take appointments at the sub-registrar office to complete the formalities. It will also reduce long queues and eliminate the possibilities of harassment and corruption, said officials.

The pilot project will be launched within a few weeks while NGDRS will be implemented across the city by August 15, they added.

Once the system is in place, the revenue department will also be able to launch the e-registration system, bringing Municipal Corporation of Delhi (MCD) and Delhi Development Authority (DDA) on the same IT-enabled platform. It will make the verification of property documents easier for sub-registrars.

"All property documents are required to be verified by MCD. Similar verification of property papers is also required by DDA. Every document has to be manually stamped, which leads to unnecessary delay and harassment," said a revenue official. "The current system is bereft of IT-based processes and solutions that ensure efficiency and transparency. The processes and procedures in Delhi are 40-50 years old while most states have achieved a higher degree of automation and faceless interface."

The LG has also emphasised on carrying out necessary changes in relevant acts to ensure that entire Delhi is treated as a single district for registry of all documents.

An official of the divisional commissioner's office said a large number of complaints received on various grievance redressal platforms were about corruption and harassment in the process of registration of documents. "People approaching the sub-registrar offices are asked to carry several copies of documents and made to wait for hours. Upon finding deficiencies in documents, the papers are kept by sub-registrars, resulting in a backlog," said an official.

Revenue officials said land records and registry were currently available on Delhi Online Registration Information System, which is an old tool. Directions have also been issued to engage a third party to speed up the scanning of old documents, said an official.

DDA: 4 more sectors eligible for consortiums under land pooling

Vibha.Sharma
@timesgroup.com

New Delhi: The Delhi Development Authority will soon issue conditional notices to land owners in four more sectors found eligible to form consortiums under the land pooling policy (LPP).

Officials said sectors 7A, 7B and 7C in Zone P-II and Sector 11 in Zone N have met the eligibility criteria for the policy, i.e., 70% contiguous land made available for development, for consortium formation. DDA will upload a notice soon on its website in this regard. "We will issue final notices to fulfil all eligibility conditions, form a consortium that will plan and pursue developers. We will only be handholding and have no role to play, except sanctioning layout plans," said an official.

Depending on feasibility, layout plans can be prepared either for a group housing society or plotted development. Sectors under Zone P-II comprise the north Delhi villages of Jindpur, Mukhmalpur and a large portion of Gadi Khasro. Sector 11 of Zone N comprises Salahpur Majara village in north-west Delhi.

Earlier, DDA had found two land parcels — Ibrahimpur in Sector 8B under Zone P2 and another in the same sector — eligible for consortium formation and received expression of interest in November. "A consortium has been formed by the land owners. We are currently at the planning stage," said the official.

At present, 105 villages, divided into six zones, have been identified for land pooling

The developments come at a time when the proposed amendments to the Delhi Development Act, which aim to empower the Centre to make land pooling mandatory even if minimum eligibility is not achieved, are yet to be approved.

At present, 105 villages, divided into six zones and further divided into 138 sectors, have been identified for land pooling. The land pooling policy was notified by DDA in September 2018. Till date, 7,100 applicants with about 7,500 hectares of land, out of a total poolable land of 19,074 hectares, have expressed interest, said a senior DDA official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक जागरण नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023 DATED----------

उपनिबंधक आफिस, नगर निगम व डीडीए में हो समान आइटी प्लेटफार्म

एलजी की ई-पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने की पहल

- 15 अगस्त से शहर में एक साथ लागू होगा नेशनल जेनरिक डाक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम
- लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति, उपराज्यपाल ने की कामकाज की समीक्षा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में भूमि संबंधी कार्यों, वसीयत समेत अन्य दस्तावेज बनवाने के लिए ई-पंजीकरण को सुगम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर राजस्व विभाग के साथ उपनिबंधक कार्यालय, एमसीडी और डीडीए को नेशनल जेनरिक डाक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनसीडीआरएस) से जोड़ा जाएगा, ताकि आमजन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। यह प्रणाली लोगों के लिए खरीद-फरोख्त, पावर ऑफ अटार्नी और वसीयत के पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे अपलोड करना, भुगतान करना और शेष औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उपपंजीयक कार्यालय में समय लेना आसान बना देगी। एनजीडीआरएस के क्रियान्वयन से लंबी कतारें भी कम होंगी और उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। इस पायलट प्रोजेक्ट को कुछ हफ्तों में ही शुरू किया जाएगा, जबकि एनजीडीआरएस को पूरे शहर में 15 अगस्त तक लागू किया जाएगा।

वीके सक्सेना

एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में 22 उपनिबंधक कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा की गई। इस दौरान उपनिबंधक कार्यालयों, एमसीडी और डीडीए को एक आम आइटी-सक्षम प्लेटफार्म पर लाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा, एक बार एनजीडीआरएस लागू हो जाने के बाद राजस्व विभाग भी एमसीडी और डीडीए को एक ही आइटी-सक्षम प्लेटफार्म पर लाकर ई-पंजीकरण प्रणाली शुरू करने में सक्षम होगा, जो बिक्री दर्ज करने से पहले उपपंजीयक के लिए संपत्ति के दस्तावेज के सत्यापन को आसान बना देगा। यह प्रमाणित करने के लिए कि दस्तावेज अवैध नहीं हैं, सभी संपत्ति दस्तावेज को एमसीडी द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है। डीडीए द्वारा संपत्ति के कागजात के समान सत्यापन की भी आवश्यकता है। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक दस्तावेज पर हाथ से मुहर लगाना पड़ता है, जिससे बेवजह देरी और उपभोक्ताओं का उत्पीड़न होता है। उन्होंने कहा कि अपने पहले के निर्देश को दोहराते हुए, एलजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी दस्तावेज की रजिस्ट्री के उद्देश्य से पूरी दिल्ली को एक जिले के रूप में माना जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक अधिनियमों में आवश्यक बदलाव किए जाएं।

काम करने की दक्षता के साथ बढ़ेगी पारदर्शिता

ई-पंजीकरण की प्रक्रिया आइटी-आधारित होगी, जिससे काम करने की दक्षता तो बढ़ेगी ही, इससे काम में भी कहीं ज्यादा पारदर्शिता नजर आएगी। दिल्ली में जमीन की खरीद-फरोख्त, पावर आफ अटार्नी और वसीयत आदि की प्रक्रियाएं चार-पांच दशक पुरानी हैं, जबकि अधिकांश राज्यों ने आटोमेशन और फेसलेस इंटरफेस जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

डीडीए ने निकाला जेलरवाला बाग इन सीटू फ्लैट्स का ड्रा

राज्य, नई दिल्ली: डीडीए ने बुधवार को अपनी झुग्गी पुनर्वास परियोजना के तहत जेलरवाला बाग अशोक विहार में इन सीटू आधार पर बने फ्लैटों का ड्रा निकाला। डीडीए मुख्यालय में आयोजित इस ड्रा में तय पात्रता के तहत 1093 लोगों को फ्लैट का आवंटन किया गया।

भाजपा सांसद डा हर्षवर्धन ने टवीट कर फ्लैट पाने वालों को इसकी बधाई दी। उन्होंने कहा कि घर मिलने की खुशी किसी उत्सव से कम नहीं होती। पीएम नरेन्द्र मोदी की हर गरीब को घर देने की प्रतिबद्धता के अनुरूप दिल्ली के झुग्गीवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का ड्रा द्वारा आवंटन किया गया। लाभार्थियों के चेहरे पर जो खुशी मैंने देखी, वह अवर्णनीय है।

अधिकारियों ने बताया कि डीडीए झुग्गीवासियों के लिए गोल्डन पार्क रामपुरा व माता जय कौर पब्लिक स्कूल प्रोजेक्ट के तहत 1665 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बना रहा है। ये 31 मई तक तैयार हो जाएंगे। जिन लोगों का आज ड्रा निकला है, उन्हें एक लाख 71 हजार रुपये फ्लैट की कीमत के रूप में जमा करने होंगे।